

1339/24 जी०

16-11-2019

कार्यालय

उत्तराखण्ड वन-सदैव आपके संग

मुख्य वन संरक्षक, निगरानी, मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकीकरण।

वन भवन, 85/87, राजपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 547 / 32-1-2(जी.आई.एस.) देहरादून, दिनांक: 30 सितम्बर, 2019

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
घनसाली (मुख्यालय-घुमेटीघार)।

विषय :- मोटर मार्गों का निकटतम राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण का नाम तथा राष्ट्रीय पार्क से हवाई दूरी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका कार्यालय पत्रांक 1259/10एम०जी० दिनांक 11-09-2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में मूलगढ़-ठेला-गण्डराखाल मोटरमार्ग का मेलगढी से पाण्डवगांव तक विस्तार तथा पिलखी नैल बौसला वनचुरी मोटर मार्ग का वनमूमि प्रस्ताव हेतु के०एम०एल० फाईल पौलिगन को तैयार कर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र की केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य की निकटतम सीमा से हवाई दूरी क्रमशः 29.5 कि०मी०, 35.7 कि०मी० GIS तकनीकी द्वारा आपके माध्यम से दी गई KML file से सन्निकट आंकलित की गई है।

भवदीय,

28/9/19

मुख्य वन संरक्षक,

निगरानी, मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकीकरण

उत्तराखण्ड, देहरादून।

स०३१० (III)

28/9/19

16.11.19

स०३१०

15/11

प्रारूप-26

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मूलगढ टेला गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढी से पांडवगांव तक विस्तार कार्य । (लम्बाई-6.825 कि०मी०)

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने अथवा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के 10.00 किमी० की परिधि के अन्तर्गत होने की दशा में लागू)

लागू नहीं

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना होगा।

ह०/-
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक

प्रारूप-27

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मूलगढ ठेला
गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढी से पांडवगांव तक विस्तार कार्य
। (लम्बाई-6.825 कि०मी०)

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने की दशा में भारतीय
वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति)

लागू नही

(नोट:-लागू होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय
उच्चतम न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न की जाय।)